क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रेस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक

क्रांति समय

RNI.No.: GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई. सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्स्योरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्षः 1 अंकः 162, शुक्रवार, 06 जुलाई, 2018, पेजः 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिसः- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

चिदंबरम से मिलकर केजरीवाल ने शुक्रिया अदा किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से उत्साहित आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के वकील रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि इस मामले में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल में चिदंबरम भी शामिल थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केजरीवाल ने बुधवार शाम पी चिदंबरम से मुलाकात कर शुक्रिया अदा किया है।

कानपुर में पकड़ा जीएसटी का सबसे बड़ा फ्रॉड, 400 करोड़ का फर्जीवाड़ा

कानपुर (एजेंसी)। जीएसटी लागू होने के एक साल बाद देश का सबसे बड़ा घोटाला कानपुर में पकड़ा गया है। जीएसटी महानिदेशालय की खुफिया विंग ने नयागंज के दो व्यापारियों को 400 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग में गिरफ्तार कर लिया है। इस बिलिंग के जरिए दोनों ने 60 करोड़ रुपये की न सिर्फ टैक्स चोरी बल्कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेकर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना भी लगा दिया। इससे पहले 21 मई को जयपुर में 58 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का खुलासा किया गया था। इस संबंध में राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छापे मारे गए थे।

फैसला दिल्ली की जनता की जीत : संजय सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी)। आप के राज्यसभा सदस्य और पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि जनता उसके हित के लिए काम करने की उम्मीद से सरकार चुनती है, लेकिन दिल्ली में चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिए जाने से जनता निराश थी, सर्वोच्च अदालत का फैसला दिल्ली की जनता की जीत है।पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा कि फैसले से साफ है कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। इन तीन विषयों को छोड़ कर, चाहे वो बाबुओं के तबादला का मसला हो या अन्य मामले हों, वे सब अब दिल्ली सरकार के अधीन आ जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान की व्याख्या मात्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल संविधान भी व्याख्या मात्र है। न्यायालय भी संविधान के बाहर जाकर निर्णय नहीं सुना सकता। उप-राज्यपाल के अधिकार यथावत हैं अब केजरीवाल को उप-राज्यपाल के असहयोग का बहाना बनाकर अपनी नाकामी छिपाना मुश्किल हो जाएगा। यानी उन्हें अब काम करने दिखाना होगा। केजरीवाल को लगता है कि यह निर्णय उनके पक्ष में है, तो अच्छी बात है। केजरीवाल अब प्रधानमंत्री पर काम न करने देने का आरोप नहीं लगा पाएंगे। दिल्ली बीते साढ़े तीन साल में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। गोयल ने चेतावनी देते हुए कहा कि केजरीवाल इस निर्णय को अधिकारियों का प्रताड़ित करने का लाइसेंस न समझ लें।

कानपुर में होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक ने मासूम भाइयों को बेरहमी से पीटा

कानपुर (एजेंसी)। होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक ने सगे भाइयों को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि दोनों से काफी देर तक उठक-बैठक भी कराई। पिटाई से दोनों छात्रों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया। पिता ने थाने में शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया। ग्वालटोली ब्रह्मदेव मंदिर के पास रहने वाले महेश गुप्ता प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनका एक पुत्र नमन गुप्ता (8) कक्षा चार और छोटा बेटा अहम गुप्ता (6) कक्षा दो में पढ़ता है। मोहल्ले में ही रहने वाले शिक्षक मिथिलेश गुप्ता दोनों बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। रोज की तरह बुधवार शाम को भी दोनों बेटे ट्यूशन पढ़ने गए थे। जब वे लौटकर आए तो उनकी हालत देख परिजनों के होश उड़ गए। नमन ने बताया कि कविता नहीं सुनाने पर टीचर ने मुझसे 400 और अहम से 50 बार कान पकड़कर उठक-बैठक कराई। इसके बाद होमवर्क पूरा नहीं करने पर डांटा और डंडे से पिटाई कर दी।

पेट्रोल 16 पैसे, डीजल 12 पैसे लीटर महंगा

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल कीमतों में एक महीने से अधिक समय बाद बढ़ोतरी की गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के बढ़ते दाम तथा रुपये में कमजोरी से ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं।

पेट्रोल की कीमत में जहां 16 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल में 12 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने ओपेक के 10 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने के बाद करीब आठ दिन तक मूल्यों में संशोधन रोका हुआ था। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 75.55 रुपये प्रति लीटर से 75.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 67.38 रुपये से 67.50 रुपये प्रति लीटर हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्रों की तीनों पेट्रोलियम विपणन कंपनियों इंडियन आयल कॉरपोरेशन , भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 26 जून से पेट्रोल , डीजल कीमतों में संशोधन नहीं किया है। इंडियन आयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने पीटीआई भाषा से कहा हमने ओपेक के फैसले के मद्देनजर पिछले कुछ से दिन से कीमतों में संशोधन नहीं किया है। हालांकि , जुलाई से 10 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन बढ़ाने के फैसले का लाभ ईरान मुद्दे की वजह से खत्म हो गया है।'' ओपेक ने जहां पिछले महीने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया , वहीं अमेरिका की ओर से भारत और चीन सहित अन्य देशों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे चार नवंबर तक ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर दें। सिंह ने कहा कि ईरान प्रतिदिन 23 से 25 लाख बैरल का उत्पादन करता है। अब दुनिया के देश इतनी मात्रा के लिए अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इससे कीमतों पर दबाव पड़ा है।

ईमानदार प्रशासन से ही स्थिरता, शांति संभव : राजनाथ

श्री नगर। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के बाद पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में शांति एवं स्थिरता एक ईमानदार , प्रभावी और कुशल प्रशासन से ही लायी जा सकती है। सिंह ने यह बात एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद कही जिसमें राज्यपाल एन एन वोहरा , राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और प्रशासन एवं पुलिस के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

मूसलाधार बारिश की चेतावनी के चलते

दिल्ली और उप्र सहित 13 राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात

नई दिल्ली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर सहित 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश की मौसम विभाग द्वारा जारी की गयी चेतावनी के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 89 टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

एनडीआरएफ की ओर से बताया गया कि इन राज्यों में बारिश के दौरान बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में 45 टीमों को तैनात कर दिया गया है। बाढ़ की आपदा के दौरान किसी भी संभावित स्थिति से निपटने में सक्षम और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त राहत एवं बचाव कर्मियों को इन टीमों में शामिल किया गया है।

इनमें से सर्वाधिक असम में 12 टीमें, बिहार में सात, गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में चार चार तथा अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में तीन तीन टीमें भेजी गयी है। दिल्ली और पंजाब में दो दो एवं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा में एक एक टीम भेजी गयी है।

एनडीआरएफ की इन टीमों ने असम सहित अन्य राज्यों में बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से अब तक 13550 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। साथ ही इन इलाकों में स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ मिलकर स्कूल तथा अन्य स्थानों पर बाढ़ की स्थिति से निपटने के बारे में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने आज से लेकर नौ जुलाई तक कोंकण एवं गोवा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मराठवाड़ा क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटक के तटीय और भीतरी इलाकों एवं पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग ने तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कनार्टक में कुछ स्थानों पर तूफान और तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका व्यक्त की है। वहीं राजधानी दिल्ली में आज दोपहर बाद कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी।

दिल्ली में अगले तीन दिनों तक आंशिक बादल छाये रहने के बाद नौ और दस जुलाई को गरज बरस के साथ बारिश की बौछारें मौसम को खुशगवार बनायेंगी। विभाग ने 11 जुलाई को दिल्ली के अधिकांश इलाकों में तूफान और तेज बारिश की आशंका जतायी है।

इस बीच आगामी 11 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। जबकि आज और कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने के बाद आठ जुलाई को यह 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद मानसून की सक्रियता में बढ़ोतरी का दौर शुरु होने पर नौ तारीख से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जायेगी। इसके 11 जुलाई को 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है।

केंद्र ने राज्यों से बच्चा चोरी की अफवाह पर पीट-पीटकर हत्या की घटनाएं रोकने के लिये कहा

नई दिल्ली। केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की अफवाहों के बाद भीड़ द्वारा पीट - पीटकर मार डालने की घटनाओं को रोकने के लिये कहा। बीते दो महीनों में बच्चा चोरी के संदेह में देशभर में 20 से अधिक लोगों को पीट - पीटकर मार डाला गया है और ताजा मामला महाराष्ट्र के धुले जिले का है जहां भीड़ ने पांच लोगों की पीट - पीटकर जान ले ली। गृह मंत्रालय ने एक परामर्श में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से '' बच्चा चोरी की अफवाहों का जल्दी पता लगाने के लिये पैनी नजर रखने और उन्हें रोकने के लिये असरदार उपाय शुरू करने '' को कहा।

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा , '' केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की अफवाहें फैलाकर भीड़ द्वारा पीट - पीटकर मार डालने की घटनाओं को रोकने के लिये उपाय करने को कहा। '' उनके अनुसार, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जिला प्रशासनों को असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करके जागरूकता फैलाने तथा विश्वास बहाल करने का निर्देश देने को कहा गया।

माल्या की 159 संपत्तियों की हुई पहचान, किंतु नहीं हो सकी कुर्क : पुलिस

नई दिल्ली। बेंगलूर पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि उसने शराब व्यवसायी विजय माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है। किंतु फेरा उल्लंघन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में पुलिस इनमें से कोई संपत्ति कुर्क नहीं कर पाई है।

बेंगलूर पुलिस ने ईडी के जरिये मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत को बताया कि वह माल्या की संपत्ति कुर्क नहीं कर पायी है क्योंकि इनमें से कुछ को मुंबई क्षेत्र के ईडी ने कुर्क कर लिया है और शेष संपत्ति परिसमापन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

इस मामले में सम्मन से बचने के कारण अदालत ने चार जनवरी को माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि एजेंसी को माल्या की ऐसी अन्य संपत्तियों को पहचान करने के लिए अधिक समय चाहिए जिन्हें कुर्क किया जा सकता है।

अदालत ने एजेंसी के अनुरोध को मान लिया और बेंगलूर पुलिस को निर्देश दिया कि वह 11 अक्तूबर तक नयी रिपोर्ट दाखिल करे।

मट्टा ने कहा, '' बेंगलूर पुलिस ने कुर्की आदेश को तामील करने के लिए यूनाइटेड ब्रेवरीज के कानूनी सलाहकार से संपर्क किया था। यह आदेश अदालत ने मई में दिया था। कानूनी सलाहकार ने बताया कि ईडी मुंबई ने इनमें से कुछ संपत्ति जब्त कर ली है तथा अन्य संपत्ति कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये आधिकारिक परिसमापक (लिक्वीडेटर) के तहत हैं।''

अदालत ने आठ मई को मामले में बेंगलूर पुलिस आयुक्त के जरिये माल्या की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिये थे और उनसे रिपोर्ट तलब की थी। अदालत ने फेरा उल्लंघन के तहत सम्मन से बचने के कारण माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया क्योंकि वह कई बार सम्मन जारी करने के बावजूद पेश नहीं हुआ।

ब्रिटेन कोर्ट ने जांच एजेंसी को दिए वसूली के आदेश

लंदन। ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या से बकाए की वसूली का प्रयास कर रहे भारत के 13 बैंकों के गठजोड़ के पक्ष में निर्णय लागू कराने के लिए प्रवर्तन का आदेश जारी किया है। माल्या पर बैंकों के साथ कर्ज में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है और वह अपने को भारत को सौंपे जाने की भारतीय एजेंसियों की ओर से दाखिल अर्जी का विरोध कर रहे हैं। इस आदेश के तहत ब्रिटेन उच्च न्यायालय के प्रवर्तन अधिकारी को माल्या (62) की लंदन के पास हर्टफोर्डशायर में संपत्तियों में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके तहत अधिकारी और उसके एजेंट को ब्रिटेन के वेलविन इलाके में तेविन नामक स्थान पर लेडीवॉक और ब्रैंबल लॉज में उनके ठिकानों में प्रवेश की अनुमति होगी।

यदि नीतीश राजग छोड़ दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं : वीरप्पा मोइली

हैदराबाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि भाजपा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हितों को कमतर कर रही है तथा यदि उनकी पार्टी जदयू राज्य में राजग सरकार से अलग होती है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने दावा किया कि तेदेपा , शिवसेना और जदयू सहित जो भी पार्टी भाजपा के साथ गई , वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। मोइली ने पीटीआई भाषा से कहा , '' उन्हें (नीतीश) लेकर वे (भाजपा) उनके हितों को कमतर कर रहे हैं। इससे नीतीश की छवि को खासा नुकसान पहुंचा है। यदि वह अलग हटते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।''

अयोध्या मंदिर-मस्जिद भूमि विवादः आज से फिर सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बाबरी मस्जिद - राम मंदिर भूमि विवाद मामले में आज से फिर से सुनवाई शुरू करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की विशेष पीठ ने 17 मई को हिन्दू संगठनों की तरफ से पेश दलीलें सुनी थीं जिनमें उन्होंने मुस्लिमों के इस अनुरोध का विरोध किया था कि मस्जिद को इस्लाम के अनुयायियों द्वारा अदा की जाने वाली नमाज का आंतरिक भाग नहीं मानने वाले 1994 के फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। अयोध्या मामले में मूल याचिकाकर्ताओं में शामिल और निधन के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व पाने वाले एम सिद्दीकी ने एम इस्माइल फारूकी के मामले में 1994 में आये फैसले के कुछ निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी।

उन्होंने पीठ से कहा था कि अयोध्या की जमीन से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामले में की गई टिप्पणियों का, मालिकाना हक विवाद के निष्कर्ष पर प्रभाव पड़ा है।

मौलवियों के विरोध के बाद कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने दी सफाई

उप्र सरकार ने मदरसा ड्रेस मामले में कदम लिये वापस

आजम खान ने यूपी सीएम पर तंज कसते हुए पूछा- क्या योगी पहनेंगे जींस?

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरूओं के विरोध के बाद मदरसा ड्रेस कोड मुद्दे पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने मंगलवार को घोषणा की थी कि मदरसा बोर्ड में एनसीईआरटी पाठयक्रम शुरू करने के बाद अब पारंपरिक कुर्ता- पायजामा के स्थान पर नया ड्रेस लागू किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरूओं ने तीखी आलोचना करते हुए इसे धर्म में हस्तक्षेप माना। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सरकार द्वारा ऐसा कोई नया कदम उठाए जाने की बात से इंकार करते हुए कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री नारायण ने अपने जूनियर मंत्री के बयान पर कहा कि यह उनकी अपनी राय हो सकती है। मदरसा दारूल उलूम फिरंगी महल ने ड्रेस कोड पर रज़ा के बयान का विरोध करते हुए कहा कि इसका निर्णय हम पर छोड़ देना चाहिए। गौरतलब है कि श्री रजा ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि मदरसों में छात्र कुर्ता पायजामा पहनते हैं , लेकिन सरकार चाहती है कि उनका ड्रेस औपचारिक हो। मदरसा ड्रेस कोड पर आजम खान ने यूपी सीएम पर तंज कसते हुए पूछा- क्या योगी पहनेंगे जींस?

क्या सजा देगी सरकार?

हालांकि इस पूरे विवाद पर सफाई देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ड्रेस कोड विवाद को नकार दिया है। लेकिन फिर भी आजम खान का बेहद तल्ख बयान इस मामले में सामने आया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि अगर मदरसे इस ड्रेस कोड को मानने से इन्कार कर देते हैं।

लागू है अघोषित आपातकाल!

सपा नेता आजम खान ने आगे कहा कि एनसीईआरटी के कोर्स/सिलिबस को मदरसों पर लागू किया जाना चाहिए। साहेब (योगी आदित्यनाथ) आप जो भी करना चाहें, आप कर सकते हैं। इंदिरा गांधी का आपातकाल क्या था और नरेंद्र मोदी का वर्तमान आपातकाल क्या है? इंदिरा गांधी का आपातकाल घोषित किया गया था जबकि नरेंद्र मोदी का आपातकाल अघोषित है। अघोषित आपातकाल, घोषित आपातकाल से ज्यादा खतरनाक है।

मास्टर प्लान के संशोधनों को स्पष्ट किया जाए : कैट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले दिनों मास्टर प्लान में किये गए संशोधनों को लेकर कॉन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखा है। बुधवार को भेजे पत्र में कैट ने मास्टर प्लान में किए गए संशोधनों को स्पष्ट करने का आग्रह किया है जिससे कि दिल्ली के लोग उन संशोधनों का पूरा लाभ उठा सकें। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने श्री पुरी को भेजे पत्र में कहा है की एलएसी के लिए एफएआर 350 प्रस्तावित किया गया है किन्तु यह स्पष्ट होना बाकी है की हर मंजिल पर ग्राउंड कवरेज कितना मिलेगा। एलएससी फ्री होल्ड संपत्ति होने के कारण से जब प्लान स्वीकृत हुआ था तब संभवतः एक मालिक रहा होगा किन्तु उसके बाद कई संपत्तियां कई बार बिकी होंगी और उसमें को-ऑनर भी होंगे। इस दृष्टि से को-ऑनर को भी संपत्ति रेगुलराइज करने का अधिकार होना चाहिए।कैट के दिल्ली प्रदेश मंत्री देवराज बवेजा और उमेश सेठ ने कहा की इसी तरह से यह भी स्पष्ट होना आवश्यक है की स्पेशल एरिया जिसमें पुरानी दिल्ली, करोल बाग, सदर बाजार, पहाड़गंज एवं अन्य क्षेत्र शामिल हैं पर कन्वर्जन शुल्क लगेगा अथवा नहीं। स्पेशल एरिया को सीलिंग से किस तरह से बचाया जाए यह भी तय होना बाकी है। कैट के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गोयल ने कहा की इसी प्रकार 1962 से पूर्व की बिल्डिंगो एवं मार्केटों की स्थिति क्या होगी, यह भी स्पष्ट नहीं है। एलएनडीओ की मार्केटों को सीलिंग से किस प्रकार राहत मिलेगी यह भी स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2007 से लेकर अब तक दिल्ली में काफी बदलाव आ गया है इस दृष्टि से सड़कों का पुनः सर्वे किया जाना चाहिए। श्री खंडेलवाल ने कहा की बदलते समय के साथ छोटी दुकानों की 24 श्रेणियों को समाप्त करना चाहिए और उनका साइज 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 50 वर्ग मीटर करना चाहिए।

स्थिति साझा नहीं कर रहे स्कूल

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार की ओर से जारी तमाम आदेशों के बावजूद निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटे की रिक्त सीटों की स्थिति साझा नहीं कर रहे। सरकार की ओर से इस बारे में फिर सेआदेश जारी कर कहा गया है कि जो स्कूल अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके साथ सख्ती बरती जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि इस मामले में जारी पूर्व के आदेश और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को गंभीरता से लिया जाए। निदेशालय की ओर से जारी आदेश में निजी स्कूलों को ऑनलाइन तरीके से विद्यालय में कक्षावार सीटों की संख्या, रिक्त सीटों की संख्या, ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटों की संख्या, रिक्त सीटों की संख्या, ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिले के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या और दिए गए।

संपादकीय

सर्वोच्चता का सवाल

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की बांछें खिल गई हैं। अदालत ने दिल्ली के उप-राज्यपाल को नसीहत देने के लिए जिस भाषा को इस्तेमाल किया है, उसे हम कड़ी फटकार भी कह सकते हैं। वैसे यह बात तो फैसला आने से पहले भी समझी जा सकती थी कि चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च होती है और उप-राज्यपाल का काम उसके हर फैसले में अड़ंगा लगाना नहीं होता और न ही उप-राज्यपाल को चुनी हुई सरकार का हर फैसला मशीनी ढंग से राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए। अदालत ने जिन सांविधानिक व्यवस्थाओं का हवाला दिया है, उससे भी सभी वाकिफ ही थे। यह व्यवस्था भी यही कहती है कि उप-राज्यपाल सिर्फ सलाह दे सकते हैं, सरकार को किसी काम के लिए बाध्य नहीं कर सकते, साथ ही विधानसभा के फैसलों के लिए उप-राज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं है। अब अदालत ने अपने फैसले में भी यही सब बातें कही हैं। दिलचस्प यह है कि इस फैसले को दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की जीत माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा इस फैसले को अपने हक में बता रही है। यहां पर बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से जो खींचतान चल रही थी, उस पर इस फैसले का कोई असर पड़ेगा? शायद हां और शायद नहीं भी। दिल्ली सरकार के किसी भी फैसले को राष्ट्रपति के पास भेजना या न भेजना अभी भी उप-राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करेगा। यानी फैसले अटकाए जाने की गुंजाइश शायद अभी भी रहे। हां, अब यह इतना आसान नहीं होगा। जब भी ऐसा मौका आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का बुधवार का फैसला सबको याद आएगा। और शायद इसी बात का ख्याल करके सरकार के फैसलों को अटकाने की घटनाओं में थोड़ी कमी आए। यह भी हो सकता है कि अब हर ऐसे मामले पर मुकदमेबाजी हो और अटकते-लटकते फैसले अदालतों में भटकते रहें। दरअसल, अदालत वैधानिक और अवैधानिक की व्याख्या कर सकती है, वह इस लिहाज से सही-गलत भी बता सकती है, लेकिन वह उस राजनीतिक उलझन को नहीं सुलझा सकती, जो दिल्ली की खींचतान का सबसे बड़ा कारण है। जरूरी यह है कि दिल्ली की जरूरतों और उसके विकास के मसलों को दलगत राजनीति से अलग किया जाए, और यह तभी हो सकता है, जब सभी सियासी दल ऐसे मसलों पर टकराव की राजनीति छोड़ें। इसके लिए जिस राजनीतिक बड़प्पन की जरूरत है, वह फिलहाल नदारद है। समस्या का जिम्मेदार इस बात को ठहराया जाना आसान है कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग दल की सरकारें हैं और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हासिल, इसलिए टकराव हो रहा है, जबकि सच यह है कि पहले कई बार ऐसी स्थितियों में दिल्ली का शासन-प्रशासन पूरे सद्भाव से चला है। इस बात को दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना होगा। पिछले कुछ समय से दिल्ली में जिस तरह की राजनीति शुरू हुई है, उसमें दोनों ही दलों के लिए वापस लौटना शायद मुश्किल हो। दिल्ली के मामले में केंद्र में सत्ताधारी दल शायद ही अपना रवैया बदलना चाहे और अगर सचमुच में वह दिल्ली सरकार के काम में रोड़े अटकाना बंद कर दे, तो शायद इससे दिल्ली सरकार की परेशानियां बढ़ जाएं। तब उसका यह बहाना खत्म हो जाएगा कि केंद्र उसे काम नहीं करने दे रहा और उस पर फैसले लेने और काम करके दिखाने का दबाव बन जाएगा।.

भीड़तंत्र का खतरा

पिछले कुछवर्षो से भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा के रूप में पाशविक सामाजिक प्रवृत्ति का उभार तेजी से हो रहा है। विशेषकर गोरक्षा के नाम पर लोग कानून को अपने हाथमें लेकर महज शक के आधार पर किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने भीड़ की बढ़ती हिंसा और हत्या की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा है कि गोरक्षा के नाम पर कोईभी व्यक्ति कानून को अपने हाथमें नहीं ले सकता। भीड़ द्वारा की गई हिंसा और हत्या कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, अपराध है, और इसे रोकना राज्यों का दायित्व है। हालांकि भारतीय समाज के सुदूर अंचलों में पहले भी भीड़ द्वारा हिंसा की जाती रही है। खासकर विधवा महिलाओं की संपत्ति हड़पने के लिए उन्हें डायन बताकर हिंसा किए जाने के तमाम मामले प्रकाश में आते थे। लेकिन इस पाशविक प्रवृत्ति का जिस तेजी से उभार हो रहा है, वह किसी भी सभ्य और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के माथे पर कालिख है। इस तरह की घटनाएं भारतीय समाज की प्रगतिशीलता के दावे को संदिग्ध बनाती हैं। लोकतंत्र द्वारा शासित समाज यदि कानून को अपने हाथ में लेकर फैसले लेने लगे तो लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील होने का खतरा साफतौर पर दिखाई देने लगता है। चिंता और हैरानी की बात है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे बच्चा चोरी का आरोप लगाकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि हिंसा धर्म और जाति को निशाना बनाकर हो रही है। अगर यह सच है तो इसे सख्ती से रोकने की जरूरत है क्योंकि इससे सामाजिक विघटन का खतरा है। हालांकि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिएसुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सभी राज्यों को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया था और साथही सभी जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अफसर नियुक्त करने को कहा था। लेकिन इस निर्देश का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण हिंसक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता गया। बहरहाल, अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। सरकार ने भी सामाजिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले संदेशों के प्रसार को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए व्हाट्सएप को चेतावनी जारी की है। उम्मीद है कि सरकार की सक्रियता से भीड़ की हिंसा पर प्रभावी अंकुश लग पाएगा।

कटाक्ष/ सहीराम

कुकुर युग का आगाज

कर्नाटक चुनावों के दौरान एक अच्छी सीख दी गई थी कि देशाभक्ति सीखनी है तो कुत्तों से सीखो। कुत्ते इन्हीं के लिए मशहूर भी रहे हैं। पर कर्नाटक चुनावों में विमर्श बदल दिया गया। बताते हैं कि यह उनकी विशेषता है। बदलना तो बहुत कुछ था, पर वे अक्सर विमर्श बदलते हुए ही पाए गए। वफादारी पर वोट नहीं मांगे जा सकते। भला कोई उम्मीदवार यह कहके वोट कैसे मांगे कि मैं कांग्रेस या भाजपा का वफादार सिपाही हूं। जनता कह सकती है कि भैया, हम कब कह रहे हैं कि अपनी वफादारी बदलो। जीत जाओगे तो अपने आप बदल लोगे। पर कोई कहे कि मैं देशभक्त हूं तो जनता वोट देने के लिए टूट पड़ेगी जैसे कह रही हो कि भैया, बड़े भाग हमारे जो आप जैसा देशभक्त मिला। इसीलिए सीख यह नहीं दी गई कि वफादारी सीखनी है तो कुत्तों से सीखो। सीख यह दी गई कि देशभक्ति सीखनी है तो कुत्तों से सीखो। पिछले कुछ वर्षो में कुत्ते राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो उठे हैं। खास तौर से जब से गुजरात के दंगों के सिलसिले में कहा गया कि कार के नीचे आकर कोई कुत्ते का पिल्ला मर जाए तो कार बैठे व्यक्ति का क्या दोष। समस्या यह रही कि तब तक विमर्श नहीं बदला था1 कुत्ते को कुत्ते की मौत मरने लायक ही माना जा रहा था। बहरहाल, इधर श्रीराम सेना के नेता प्रमोद मुत्तालिक ने इस कुकुर विमर्श को और आगे बढ़ाया है। गौरी लंकेश की हत्या के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जरूरी थोड़े ही है कि कोई कुत्ता भी मर जाए तो प्रधानमंत्री उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। गौरी लंकेश की हत्या पर एक ट्रोल वीर ने कुछ इसी तरह की बात कही थी कि एक कुतिया मर गई तो देखो पिल्ले कैसे बिलबिला रहे हैं। तब पता चला था कि उसे बड़े-बड़े दिग्गज फॉलो करते हैं। जो भी हो यह कुकुर विमर्श पुष्पित-पल्लवित होकर बड़े विमर्श का रूप ले चुका है। जाहिर है इसे भी समृद्ध बनाने में शासकों का ही ज्यादा योगदान रहा है। शासकों में सब शामिल हैं छुटभैये भी और केंद्रीय मंत्री भी। दिक्कत यह है कि कर्नाटक में दी गई सीख का अनुसरण कोई नहीं कर रहा कि देशभक्ति सीखनी है तो कुत्तों से सीखें। वैसे इस पुरानी सीख का अनुसरण कर भी कौन रहा है कि वफादारी सीखनी है तो कुत्तों से सीखें।

समर्थन मूल्य और किसानों की दुविधा

सोमपाल शास्त्री, पूर्व कृषि मंत्री

बुधवार को घोषित खरीफ की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार का एक बड़ा दांव है। इस घोषणा में चार-पांच महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं, जिसका विश्लेषण जरूरी है। पहली तो यह कि सत्तारूढ़ दल ने 2014 के चुनावी घोषणापत्र में यह लिखित वचन दिया था कि वह स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को सत्ता में आते ही लागू करेगी, जिसमें किसानों को सी-2 लागत (फसल की हर मद को जोड़ते हुए कुलजमा लागत) के ऊपर 50 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही गई थी।

दूसरी बात, 2015 में जब इस संदर्भ में एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई, तब अपने जवाब में केंद्र सरकार ने एक शपथ पत्र दाखिल किया कि यह व्यावहारिक नहीं है और वर्तमान संसाधनों में संभव भी नहीं है। इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं- एक, चुनावी वादा एक अलग चीज थी, दूसरा, इसे लागू करने की इच्छा के बावजूद उपलब्ध संसाधनों में इसे पूरा करना संभव नहीं था। इसलिए पूरे मामले ने यह मोड़ ले लिया कि पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया। बार-बार यह कहा जाता रहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट काफी पहले आ गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों पर बिल्कुल अमल नहीं किया गया। मगर सच है कि बाद में भी यह नहीं किया जा सका। अभी तक इस मामले में ज्यादा नहीं हो सका, तो अगले बजट में भी कुछ नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वह आचार संहिता से पहले का बजट होगा। हां, इस बार बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही जरूर गई, लेकिन उस वक्त अमल नहीं किया गया। कहा गया कि आगामी खरीफ से इस पर अमल होगा। इसलिए इस मौके पर उम्मीद बनना स्वाभाविक ही था।

पहले आमतौर पर सी-2 लागत के ऊपर 10-12 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती थी। उसके मुकाबले सत्तारूढ़ दल ने 50 प्रतिशत की बात की, जिसकी चर्चा स्वामीनाथन आयोग में भी की गई है। मगर इन वर्षों में एक और चीज यह हुई है कि सी-2 लागत की परिभाषा ही बदल दी गई है। उसका नया बेंचमार्क नीचे कर दिया गया है।

पिछले चार वर्षों में जितने समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं, उनमें केवल दो जिंसों यानी धान और गेहूं को छोड़कर सभी फसलों के बाजार मूल्य सभी आठों मौसम में समर्थन मूल्य के नीचे रहे हैं। जबकि समर्थन मूल्य की प्रतिबद्धता या आधार यह है कि यदि बाजार में समर्थन मूल्य के नीचे किसी जिंस की कीमत जाती है, तो सरकार किसी कीमत पर उस दाम को नीचे नहीं गिरने देगी और तय कीमत पर किसानों से खरीदेगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट में एक वाक्य सब बार-बार दोहराते हैं कि आशा की जाती है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचा मूल्य प्राय: मिलता रहेगा। यदि ऐसी स्थिति आती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बाजार के भाव जाते हैं, तो सरकार उसकी खरीद के जरिए उतना भाव तो सुनिश्चत कराएगी ही। मगर इन चार वर्षों में यह भी नहीं मिला। यानी एक तो लागत का स्तर बदला गया, चार साल तक वादा पूरा नहीं किया गया, घोषित समर्थन मूल्य नहीं मिले, फिर अब किस आधार पर यह विश्वास किया जाए कि जो घोषणा की गई है, वह मूल्य किसानों को मिल जाएगा?

न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में काम करता है। दरअसल, खेती की एक विशेष परिस्थिति है। उसका एक अलग स्वभाव है। सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करने वाले तमाम श्रमिकों व कुशल कार्यकर्ताओं को एक निश्चित रकम तय अवधि में मिलती रहती है। यानी उसकी आय का स्रोत लगातार प्रवाहित होता रहता है। मगर किसानों के नगदी-प्रवाह में दिक्कत है। जिस दिन से वह खेत जोतकर बुआई की तैयारी करता है, तब से लेकर जब तक फसल नहीं आ जाती, उसके दोतरफा व्यय चलते रहते हैं। यानी खेती पर भी खर्च होता है और घर-परिवार पर भी, जबकि उसको आय छह महीने के बाद होती है। इन तमाम खर्चों और आय की प्रतीक्षा में किसानों की सहनशीलता जवाब देने लगती है। इसलिए बाजार में जो भी मूल्य मिलता है, उस पर वह अपनी फसल बेचने को तैयार हो जाता है। यह विवशता की बिक्री है। उसकी इस परिस्थिति का लाभ ही जमाखोर उठाते हैं और फिर उपभोक्ताओं को कई-कई गुना अधिक कीमत पर बेचते हैं। इस जाल को तोड़ने के लिए ही एमएसपी ईजाद की गई थी। 1965 में यह दो जिंसों पर लागू होने के साथ शुरू हुआ, मगर अब जिंसों की संख्या बढ़कर 20 से अधिक हो चुकी है।

जाहिर है, आदर्श स्थिति यही है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20-25 प्रतिशत ऊपर दाम मिले। इसके लिए किसानों की मांग और बाजार में इस प्रकार के सुधार की अपेक्षा रहती है कि किसानों को वहां स्वत- यह दाम मिल जाए। न सरकार को फसल खरीदनी पड़े, न भंडारण करना पड़े, न कोई भ्रष्टाचार हो और न किसानों को कठिनाई हो। मगर मुश्किल यह है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के तमाम सुधारों के बाद भी किसानों के बाजार के ऊपर उसी तरह के प्रतिबंध आयद हैं। वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र अनाज नहीं ले जा सकते, तय मात्रा से अधिक जमा नहीं कर सकते, और तो और, निर्यात भी नहीं कर सकते। अभी भी सरकारी मंडियों में एकाधिकार के कारण किसानों का जमकर शोषण होता है।

स्पष्ट है, एमएसपी की व्यवस्था तो रहे, लेकिन बाजार की परिस्थिति भी ऐसी बने कि किसान को स्वत- जिंसों के मूल्य ज्यादा मिलें। और अगर उससे कम होता है, तो एमएसपी की मजबूत प्रणाली उसे थाम ले।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

> खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाना एक देर से हुआ फैसला है और किसान की नजर से देखें, तो यह बहुत दुरूस्त भी नहीं है।

महिला सुरक्षा

भस्मासुर बनती मर्दवादी सोच

हर्षदेव

और अब मंदसौर! वही नीचता, वैसी ही अमानवीयता और वीभत्सता कि धरती में समा जाने की जुगुप्सा हो उठे। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तेज' की हांक लगाने वाले भारत को स्त्रियों के लिए दुनिया वालों ने पृथ्वी का सबसे असुरक्षित और खतरनाक देश ठहराया तो गलत क्या किया? 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' जैसे लुभावने नारे भी हमने गढ़े हैं, फिर किस वजह से हमको ऐसी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है! क्या इसका कारण हमारी सोच और आचरण में भारी अंतर नहीं है!

पिछले सप्ताह मंदसौर की त्रासद घटना ने थॉम्पसन रॉयटर्स नाम की विश्व संस्था के सर्वेक्षण 'महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश' के कलंक का सच साकार कर दिया। इस नतीज़े तक पहुंचने का आधार मुख्यत: तीन मुद्दे रहे-पहला, सांस्कृतिक और परंपरागत प्रथाएं; दूसरा, यौन हिंसा और उत्पीड़न का स्थायी खतरा और तीसरा, घरेलू यौन दासता। यह सर्वेक्षण मार्च 26 से 4 मई के बीच किया गया। इस अध्ययन में राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों और स्त्रियों की तस्करी के साथ ही यौन व्यापार जैसी समस्याओं का ध्यान भी रखा गया।

पिछले आठ वर्ष में महिला सुरक्षा के मामले में हमारा ग्राफ़ लगातार गिरता रहा और अंतत: हम अंतिम पायदान तक जा पहुंचे। यहां तक कि अफगानिस्तान और सीरिया का स्थान दूसरा और तीसरा तथा पाकिस्तान जैसे दकियानूस देश का छठवां बताया गया। कुछ अन्य पहलुओं को भी शामिल किया गया, जैसे बदला लेने के लिए की जाने वाली यौन हिंसा, घर में बलात्कार, बाल विवाह, जबरन शादी, और पीड़ित महिला को न्याय मिलने में रुकावटें। इन सभी विषयों के कारण भी भारत को अव्वल जगह हासिल हुई।

महिला कल्याण और बाल विकास मंत्रालय ने हालांकि इस अध्ययन का आधार अवैज्ञानिक माना है। उसने अपने एतराज में कहा कि परम्परागत प्रथाओं में भ्रूण हत्या, बाल विवाह, जबरन शादी, शारीरिक अंगों को विकृत करने जैसी बातें भी इसमें शुमार कर ली गई हैं। कुछ पुरुषवादी संगठनों ने तो यहां तक कहा कि यह सर्वेक्षण अतिरंजित और विदेशियों द्वारा देश का अपमान है। लिहाज़ा बेहतर होगा कि हम खुद अपने रेकॉर्ड की जांच-पड़ताल कर लें। पहले पारिवारिक-सामाजिक हकीकत- 1. हर दिन 2000 कन्या भ्रूण हत्याएं की जाती हैं देश में, 2. एक साल में बलात्कार के 35 हज़ार से ज्यादा मामले दर्ज़ किए जाते हैं, 3. 71 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं, 4. लगभग 44 फीसद लड़कियों का विवाह नाबालिग उम्र में ही कर दिया जाता है, 5. लड़कों की संख्या लड़कियों से करीब नौ करोड़ अधिक है, 6. तलाक़ के कई लाख मुकदमे अदालतों में बरसों से फैसले के इंतजार में धूल खा रहे हैं (पिछले साल 19 वर्ष तक कानून के जंगल में भटकने के बाद तलाक़ के एक ऐसे मामले का फैसला आया, जिसमें पति-पत्नी केवल 20 दिन ही साथ रहे थे और 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 32 साल बाद 85 की उम्र के बुजुर्ग को तलाक़ की मंजूरी दी), 7. करीब 23 लाख महिलाएं ऐसी हैं, जिनको तलाक़ दिए बिना ही पति ने छोड़ दिया है, 8. अनेक राज्यों में प्रेम विवाह करने वालों को सामाजिक-पारिवारिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, यहां तक कि खाप पंचायत जैसे गैर कानूनी गुट और 8. आज भी दहेज़ की घृणित बुराई को निभाना शादी की जरूरी शर्त बना हुआ है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा और अन्याय के प्रति राजनीतिक रवैये की पड़ताल भी जरूरी है। कश्मीर के कठुआ में हुई घटना में सत्ताधीशों का चरित्र उजागर हुआ। इसी तरह जब हरियाणा में 'बाबा' गुरमीत सिंह या जोधपुर में 'संत' आसाराम के बलात्कार के गुनाह सामने आए तो बचाव में सबसे पहले नेता मैदान में उतरे। यह कृत्य देश को शर्मसार करने वाला था। दरअसल हमारा समाज ही बीमार हालात का शिकार हो चुका है। तभी तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधा जैसे हर सामाजिक मामले में हमारा ग्राफ़ निरंतर गिरावट दर्ज कर रहा है। हम बांग्लादेश तक से पिछड़ गए हैं। महिला सुरक्षा की स्थिति पर विचार करें तो सबसे पहले अपने पुरुषवादी वर्चस्व की ईमानदार पड़ताल करनी होगी। 21वीं सदी में भी स्त्री पददलित क्यों बनी हुई है! गरीब और संपन्न सभी परिवारों में लड़कियों का बचपन से ही दमन किया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवहार बचपन से ही पुरुष वर्चस्व स्थापित कर देता है। लड़कियों में असुरक्षा का स्थायी भावबोध भी बचपन में ही पैदा कर दिया जाता है। किसी भी सभ्य-शिक्षित देश में कन्या भ्रूण हत्या इस तरह आम नहीं है।

यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या हाल के वर्षों में महिलाएं ज्यादा असुरक्षित हुई हैं! बच्चियों के मामले में तो यह इजाफा भयावह है। अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 में दुष्कर्म की करीब 11 हजार घटनाएं हुईं, जो 2016 में बढ़कर 20 हजार के लगभग पहुंच गईं। जरूरी है कि इसके कारणों की थोड़ी पड़ताल की जाए। निकट अतीत में हमने समाज में मर्दवादी सोच को जिस तरह बढ़ावा दिया है, वह भस्मासुर बनती इस समस्या का एक बड़ा कारण प्रतीत होता है। इससे समाज में संवेदनहीनता बढ़ी है। वैज्ञानिक युग में आदिमयुगीन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर मनुष्य के विवेक के हरण का यह दुष्परिणाम है। समाज को समय रहते इस पर विचार करना होगा।

बादल चोरी

बेवजह है ये आरोप या..

राजीव मंडल

कीमती सामान या किसी की रचना चुराने के आरोप तो हमने कई बार सुने हैं, मगर इस बार चोरी का आरोप चकित भी करता है और चिंतित भी। ईरान के एक सैन्य जनरल ने इस्त्रइल पर अपने देश के बादल और बर्फ चुराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस्त्रइल, ईरान के मौसम से छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके चलते देश में बारिश नहीं हो रही। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल और देश के सिविल डिफेंस ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख गुलाम रजा जलाली का कहना है कि ईरान में हो रहा जलवायु परिवर्तन शक के घेरे में है। इसमें विदेशी हस्तक्षेप अहम रोल निभा रहा है। इस्त्रइल और एक अन्य देश इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर बादल तो छाएं लेकिन बारिश न करें। तो क्या ईरान के किसी शीर्ष पद पर बैठे शख्स का इस तरह का आरोप लगाना सचाई के नजदीक है? मगर भूगोलविद् की मानें तो रूस में बादल को जगह से हटाने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर बड़े पैमाने पर इसे अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अस्थायी तौर पर बादल को विखंडित करने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल करने का चलन कुछ विकसित देशों में जरूर है। फिर भी इस आरोप ने एक बार फिर पानी को लेकर विभिन्न देशों के बीच तनाव को सतह पर ला दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे बुतरस घाली ने तो लगभग तीन दशक पहले बहुत गम्भीरता से यह बात रखी थी और जिम्मेदारी के साथ कहा था कि ''अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध लड़ा गया तो वो पानी के लिए लड़ा जाएगा।' उनसे भी आगे जाकर 1995 में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष इस्माइल सेराग्लेडिन ने कहा था ''इस शताब्दी की लड़ाई तेल के लिए लड़ी गई है, लेकिन अगली शताब्दी की लड़ाई पानी के लिए लड़ी जाएगी।'

नियंतण्र तौर पर पानी की घोर कमी से हर कोई अच्छे से वाकिफ है। भारत ही नहीं विदेशी मुल्कों मसलन- अमेरिका से लेकर मध्य पूर्व और अफ्रीकी महाद्वीपों के कई देश भी पानी की समस्या से ग्रसित हैं। अमेरिका के तो कई इलाके सूखे की कमी झेल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर पानी की समस्या कई सालों पुरानी है। प्रसिद्ध भूगोलविद विल्बर्ट स्काइट-जो टेनेसी वैली कापरेरेशन के अध्यक्ष थे-उनका कहना था कि नियंतण्र शांति (ग्लोबल पीस) को काफी हद तक पाया जा सकता है अगर हम पानी की समस्या को सुलझा लें तो। उनकी बात सोलह आने सच है। अमेरिका और कनाडा के बीच पानी को लेकर काफी तनाव रहता है। अफ्रीकी देशों के बीच भी विवाद और तनाव होते हैं। उदाहरण के लिए राइन नदी कई देशों से होकर गुजरती है। उसको लेकर भी कई देशों में तनाव जैसे हालात हैं। बांग्लादेश भी भारत पर पानी नहीं देने का आरोप लगाता है। चीन के बारे में भारत के ऐसे ही आरोप हैं। किंतु यह सब कुछ ''सरफेश वाटर शेयरिंग' का विवाद है। वैसे भी जहां किसी चीज की कमी होती है तो वहां प्रतिस्पर्धा होगी और जहां प्रतिस्पर्धा होगी वहां संघर्ष होगा। हालांकि ईरान में इसके पहले भी 2011 में पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा था कि पश्चिमी देशों के चलते ईरान में सूखा पड़ा हुआ है। इस लिहाज से अंतरराष्ट्रीय शांति और सौहार्द के लिए पानी की समस्या को जल्द-से-जल्द निपटाया जाना बेहद जरूरी है। संसाधन के विकास व उसके समान वितरण को लेकर विशेष प्रयास करने की जरूरत है। जल संरक्षण के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक करने की जरूरत है। नगरपालिकाओं को पानी के संरक्षण को लेकर उपाय ढूंढने होंगे, साथ ही पानी के रि-साइकल के तौर-तरीकों को अमल में लाना होगा। लापरवाह जल प्रबंधन की काट तलाशनी होगी। दरअसल, हमारे देश में जैसे-जैसे शहरों का फैलाव होता चला गया या फिर नई जगह पर नये शहरों को बसाया जाने लगा, उसके परिणामस्वरूप जलस्तर लगातर नीचे जाने लगा। इस अंधाधुंध विकास की होड़ और पानी के इस्तेमाल को लेकर सख्त कानून के अभाव में दिल्ली और देश के बाकी इलाके में प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन जारी है। बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण के दौरान भारी मात्रा में जमीन से पानी निकालने से पूरे इलाके का जलस्तर नीचे जा रहा है। ईरान के आरोप को भले सतही तौर पर लिया जाए, परंतु पानी को लेकर तनाव और संघर्ष के संकेत तो दिखने शुरू हो गए हैं।

शेयर बाजार में दो दिन से जारी तेजी का सिलसिला थमा, सेंसेक्स 71 अंक टूटा

मुंबई। बंबई शेयर बाजार में दो दिन से जारी तेजी का सिलसिला आज थम गया और सेंसेक्स 71 अंक टूटकर 35,574.55 अंक पर आ गया। चीन के निर्यात पर अमेरिकी शुल्क लागू होने से पहले अन्य एशियाई बाजारों में गिरावट से सेंसेक्स नीचे आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज 2.53 प्रतिशत टूट गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक विशाल फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवा लाने तथा ई-कॉमर्स क्षेत्र में उतरने की घोषणा की है।

टिकाऊ उपभोक्ता सामान, रीयल्टी, आईटी, धातु, प्रौद्योगिकी, फार्मा, पूंजीगत सामान, बिजली और तेल एवं गैस कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। ब्रोकरों ने कहा कि विदेशी कोषों की निकासी तथा कमजोर रुपये से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई। चीन के उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क शुक्रवार से लगने जा रहा है। इससे ज्यादातर एशियाई बाजारों में गिरावट आई। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स मजबूती के रुख के साथ खुलने के बाद जल्द नकारात्मक दायरे में आ गया। इसने 35,517.79 अंक का निचला स्तर भी छुआ। अंत में सेंसेक्स 70.85 अंक या 0.20 प्रतिशत के नुकसान से 35,574.55 अंक पर बंद हुआ। एक समय यह 35,748.26 अंक के उच्चस्तर तक भी गया। इससे पिछले दो सत्रों में सेंसेक्स 380.99 अंक चढ़ा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 20.15 अंक या 0.19 प्रतिशत के नुकसान से 10,749.75 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 10,726.25 से 10,786.05 अंक के दायरे में रहा। इस बीच, शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल शुद्ध रूप से 284.58 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 611.01 करोड़ रुपये की लिवाली की।

एयर इंडिया ने ताईवान का नाम चीनी ताइपे किया, चीन ने किया स्वागत

नयी दिल्ली/बीजिंग। सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया ने सरकार के निर्देश पर अपनी वेबसाइट पर ताईवान का नाम बदलकर चीनी ताइपे कर दिया है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। चीन ने एयरइंडिया के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि वहां परिचालन कर रही कंपनियों को उसके (चीन के) नियमों का पालन करना चाहिए तथा उसकी स्वायत्तता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। चीन ने विभिन्न वैश्विक विमानन कंपनियों द्वारा ताईवान को अलग क्षेत्र बताये जाने पर आपत्तियां व्यक्त की थी। इसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस और एयर कनाडा जैसी कंपनियों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर जानकारियों में संशोधन किया। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि वेबसाइट पर ताईवान का नाम बदलने में विदेश मंत्रालय से मिले सुझाव का पालन किया गया है। एयर इंडिया के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लु कांग ने कहा कि चीन इसका स्वागत करता है। उन्होंने कहा, 'इस मुद्दे पर हमारी स्थिति स्पष्ट है। भारत एवं अन्य देशों को भी इस मुद्दे पर हमारी स्थिति के बारे में स्पष्ट रहना चाहिए।''

प्रौद्योगिकी कंपनी हंगरबॉक्स ने 45 लाख डॉलर की पूंजी जुटाई

नयी दिल्ली। कंपनियों को खाद्य उत्पादों एवं उससे जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी कंपनी हंगरबॉक्स ने दक्षिण कोरिया की न्यूफ्लस और भारतीय की सबरे कैपिटल की अगुवाई में 45 लाख डॉलर (करीब 31 करोड़ रुपये) जुटायी है। हंगरबॉक्स ने अपने बयान में यह जानकारी दी। हंगरबॉक्स ने बयान में कहा कि ए श्रृंख्ला के इस वित्तपोषण दौर में सिंगापुर की लॉयनरॉक कैपिटल और इंफोसिस के सह - संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की भी भागीदारी रही। पूंजी का उपयोग भारत के साथ - साथ दक्षिणपूर्वी एशियाई बाजारों में कंपनी के विस्तार में किया जाएगा। हंगरबॉक्स 2016 में शुरू हुई थी और वर्तमान में चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली- एनसीआर , जयपुर और कोलकाता में परिचालन कर रही है। यह देशभर में कंपनियों को खाद्य उत्पाद और उससे जुड़े समाधान प्रदान करती है। यह उपभोक्ताओं को ई- कैटरिंग, ई - फूड कोर्ट, ई - कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं देती है। कंपनी के सीईओ और सह - संस्थापक संदीपन मित्रा ने कहा , ÷ हम अपने कारोबार में तेज विस्तार देख रहे हैं। 6 महीने से भी कम समय में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी होकर 400 से अधिक हो गयी है। रोजाना ऑर्डरों की संख्या 1,20,000 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गया है।

ड्राइविंग लाइसेंस पहचानपत्र के तौर पर स्वीकार करेगा रेलवे

नयी दिल्ली। ट्रेन में यात्रा के दौरान अपना पहचान पत्र गुम होने को लेकर चिंतित हैं तो अब आपको इसे लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने कहा है कि वह अब आपके आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट प्रतियां स्वीकार करेगा, बशर्ते वह डिजीलॉकर में स्टोर हो। डिजीलॉकर सरकार द्वारा संचालित एक डिजिटल स्टोरेज सेवा है जिसमें भारतीय नागरिक क्लाउड पर अपनी कुछ आधिकारिक दस्तावेज स्टोर कर सकते हैं। रेलवे ने अपने सभी जोनल मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को सूचित किया है कि ऐसी सेवा के लिए इन दो पहचान प्रमाणों को यात्री के वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

रिलायंस शुरू करेगी फाइबर ब्राडबैंड सेवा, ई-कॉमर्स में भी उतरने की तैयारी

मुंबई (एजेंसी)

निःशुल्क कॉलिंग और सस्ती दर पर तीव्र मोबाइल इंटरनेट सेवा की पेशकश से भारत के दूरसंचार उद्योग की सूरत बदलने वाले देश के सबसे धनी व्यक्ति एवं रिलायंस उद्योग समूह के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने 1100 शहरों में 'हाईस्पीड' फिक्स्ड लाइन ब्राडबैंड सेवा शुरू करने की आज घोषणा की। उन्होंने ई-कॉमर्स क्षेत्र में उतरने की योजना की भी घोषणा की। अंबानी ने कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों से कहा कि ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन जैसे पुराने कारोबार को मजबूत करने के साथ साथ नये क्षेत्रों में कारोबार के विस्तार से समूह की आय 2025 तक दो गुना कर 125 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 'जियो गीगाफाइबर सर्विस' के लिए 15 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने सेवा की शुरुआत के समय के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इस सेवा के तहत एक ही फाइबर केबल के जरिये टेलीविजन पर अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इंटरटेनमेंट, वॉयस एक्टिवेटेड असिस्टेंस, वर्चुअल रियल्टी गेमिंग, डिजिटल शॉपिंग आदि समेत स्मार्ट होम समाधान भी मुहैया कराये जाएंगे। उन्होंने कहा, ''अब हम 1100 शहरों में घरों, व्यापारियों, छोटे एवं मध्यम उद्योगों और बड़े उद्योगों को सबको एक साथ फाइबर से जोड़ेंगे और सर्वाधिक उन्नत फाइबर-बेस्ड ब्राडबैंड समाधान मुहैया कराएंगे।'' अंबानी ने कहा कि आने वाले सालों में जियो फिक्स्ड लाइन ब्राडबैंड के मामले में भारत को शीर्ष पांच देशों में से एक बना देगी। उन्होंने इस सेवा की दरों की भी जानकारी नहीं दी।

उन्होंने कहा, ''हम अभी हजारों घरों में इसका बीटा परीक्षण कर रहे हैं। जहां भारत मोबाइल ब्राडबैंड के मामले में पहले स्थान पर पहुंच चुका है, वहीं हम फिक्स्ड-लाइन ब्राडबैंड में काफी पीछे हैं। इस मामले में वैश्विक आधार पर हम 134वें स्थान पर हैं। फिक्स्ड लाइन में खराब ढांचागत संरचना इसका मुख्य कारण है।'' उन्होंने कहा कि देश भर में मोबाइल एवं ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल संरचना पहल पर पहले ही 2,50,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका है। अब घरों तक फाइबर ब्राडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचेगा।

सितंबर 2016 में शुरुआत के बाद जियो ने देश को सबसे अधिक मोबाइल डेटा की खपत करने वाला देश बना दिया। अंबानी ने कहा कि जियो के ग्राहकों की संख्या 21.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है जबकि उसने अब तक 2.5 करोड़ से अधिक जियो फोन बेचे हैं। अंबानी ने कम से कम समय में 10 करोड़ जियो फोन उपभोक्ता का भी लक्ष्य तय किया। उन्होंने जियो फोन मानसून हंगामा शुरू करने की भी घोषणा की। यह योजना 21 जुलाई से शुरू होगी और इसके तहत महज 501 रुपये में फीचर फोन के बदले जियो फोन लिया जा सकेगा। उन्होंने दूसरी पीढ़ी के जियोफोन की भी घोषणा की। इसमें फेसबुक, व्हाट्सऐप और यूट्यूब भी होंगे। इसकी बुकिंग 2,999 रुपये में 15 अगस्त से की जा सकेगी।

अंबानी ने कहा रिलायंस कंपनी ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से कारोबार विस्तार करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता कारोबार भी ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन कारोबार की तरह योगदान देने वाला है। अंबानी ने कहा, 'भारत जब उच्च गति से आर्थिक वृद्धि की यात्रा शुरू करने वाला है और 2025 तक अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने वाला है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस अवधि में रिलायंस का आकार दोगुने से अधिक होगा।' उन्होंने कहा कि जियो ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुनर्परिभाषित किया है। उन्होंने कहा जियो के कारण देश की डेटा खपत 128 करोड़ जीबी प्रति माह से बढ़कर 240 करोड़ जीबी प्रति माह से भी आगे निकल गयी है। अंबानी ने कहा कि कंपनी ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, 'जैसा कि रिलायंस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म कंपनी बनते जा रही है, हमें वृद्धि के सर्वाधिक अवसर एक हाइब्रिड यानी ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने में दिखते हैं।'' उन्होंने कहा, 'हम रिलायंस रिटेल के बाजार को जियो की डिजिटल संरचना एवं सेवा से जोड़कर ऐसा कर सकेंगे।''

कंपनी के पारंपरिक कारोबार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिलायंस विश्व के सबसे बड़े पैराक्सिलीन संयंत्र, पेटकोक गैसीफिकेशन संयंत्र और ऑफ-गैस क्रैकर की शुरुआत करने के साथ ही अपना सबसे बड़ा निवेश पूरा करने वाली है। इस साल के अंत तक एक ब्यूटाइल रबर संयंत्र भी शुरू करने की योजना है।'' अंबानी ने खनिज ईंधनों की जगह नवीकरणीय ऊर्जा माध्यमों की तरफ बढ़ते रुझान का जिक्र करते हुए कहा कि हम ईंधनों को उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोरसायन उत्पाद में बदलेंगे। उन्होंने कहा, 'हमारा हाइड्रोकार्बन कारोबार भविष्य के लिए तैयार है।'' अंबानी ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन की 'रूरल ट्रांसफॉर्मेशन' मुहिम किसानों बाजार से बेहतर ढंग से जोड़ने में लगी है। उन्होंने कहा कि इससे अब तक 15 राज्यों के 13,500 गांवों में लोगों को फायदा हो रहा है।

जनता पर महंगाई की मार, 36 दिन के बाद फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल दाम

बिजनेस डेस्क। तेल कंपनियों ने करीब 1 महीने बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ौतरी कर दी है। इससे पहले इस अंतराल में करीब 22 बार पेट्रोल और 18 बार डीजल के दाम तेल कंपनियों ने कम किए थे। आज महानगरों में पेट्रोल की कीमत 16 से 17 पैसे बढ़ गई है, जबकि डीजल के दामों में 10 से 12 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 75.71 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं जबकि मुंबई में दाम 83.10 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 78.39 और 78.57 रुपए प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमतों में पिछले कुछ समय में तेजी देखी जा रही है और अब डीजल के दाम दिल्ली में 67.50 रुपए प्रति लीटर दाम हो गया है। आज यह दाम 12 पैसे प्रति लीटर तेज है। मुंबई में डीजल के दाम 71.62 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। कोलकाता और चेन्नई में डीजल के दाम 70.05 और 71.24 रुपए प्रति लीटर क्रमशः हो गया है।

किसानों को मिला उपहार, दो लाख तक का कृषि ऋण माफ कर दिया

बेंगलुरु।

कर्नाटक सरकार ने अपने घोषणा पत्र को अमल में लाते हुए किसानों के लिए दो लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ कर दिया है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने गुरुवार को कांग्रेस -जद (एस) गठबंधन सरकार के पहले बजट में 34,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की। विधानसभा में बजट प्रस्ताव पेश करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने ऋण की राशि को दो लाख रुपए तक सीमित किया है क्योंकि इससे ऊंचे मूल्य के फसल ऋण को माफ करना 'सही' नहीं होगा। कुमारस्वामी के वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने कहा है कि फसल ऋण माफी योजना से किसानों को 34,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। जद (एस) ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कृषि ऋण माफी योजना की वजह से राज्य सरकार पर पडने वाले भारी बोझ के मद्देनजर कुमारस्वामी ने पेट्रोल पर कर की दर में 1.14 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.12 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने देसी शराब सभी 18 स्लैब पर आबकारी शुल्क में चार प्रतिशत वृद्धि का भी प्रस्ताव किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह अपनी सरकार बनने पर कृषि ऋण को 24 घंटे में माफ करने का वादा किया था। उन्होंने कहा है कि हालांकि, राज्य के लोगों ने किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया है, लेकिन मुझे गठबंधन सरकार बनाने के लिए अच्छा अवसर मिला और साथ ही गठबंधन में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि पहले चरण में उन्होंने 31 दिसंबर, 2017 तक सभी चूक वाले फसल ऋणों को माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के खातों में ऋण की राशि या 25,000 रुपए , जो भी कम हो, डाले जाएंगे। इससे समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को फायदा होगा।

छोटे कारोबारियों को राहत के संकेत, आर.सी.एम. को टाल सकती है सरकार

बिजनेस डेस्क। जी.एस.टी. को लागू हुए एक साल हो गया है। इस एक साल के सफरनामे में जी.एस.टी. की दरों में काफी बदलाव हुए हैं। अब सरकार ने टैक्स घटाने का वादा दोहराते हुए कहा कि इसमें छोटे कारोबारियों को और सहूलियत दी जाएगी। इसके तहत कर चोरी रोकने का हथियार माने जा रहे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) को सरकार ने फिलहाल टाले जाने का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक जी.एस.टी. के तहत 1.12 करोड़ कारोबारी पंजीकृत हैं। सरकार को इनसे 80 फीसदी तक राजस्व प्राप्त होता है। 1.12 करोड़ में से 90 लाख छोटे कारोबारी हैं जिनसे सरकार को 20 प्रतिशत राजस्व मिलता है। सूत्रों के अनुसार जी.एस.टी. में अभी तक रिटर्न और रिफंड की परेशानियां दूर नहीं हुई हैं। ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होने से छोटे कारोबारियों में नाराजगी बढ़ सकती है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से पंजीकृत कारोबारियों पर बोझ बढ़ेगा और वे गैर-पंजीकृत डीलरों से खरीद कम करेंगे। वैसे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तौर-तरीकों को लेकर आखिरी फैसला जी.एस.टी. परिषद ने लेना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ जी.एस.टी. में स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) और स्रोत पर कर संग्रहण (टी.सी.एस.) को पहले भी टाला जा चुका है। अब यह छूट 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है।

सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त

बिजनेस डेस्क।

मजबूत वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण कारोबारियों की निरंतर लिवाली से सोने के भाव में दूसरे दिन भी तेजी बनी रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 10 रुपए बढ़कर 31,580 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, औद्योगिक इकाइयों एवं सिक्का निर्माताओं का उठाव बढ़ने से चांदी 690 रुपए उछलकर 40,600 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। कारोबारियों ने कहा कि हाजिर बाजार में स्थानीय आभूषण निर्माताओं की निरंतर लिवाली और वैश्विक स्तर पर बेहतर रुख से सोने में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में, सोना 0.34 प्रतिशत बढ़कर 1,256.50 डॉलर प्रति औंस पर रहा जबकि चांदी 0.37 प्रतिशत चढ़कर 16.06 डॉलर प्रति औंस पर रही। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 10-10 रुपए बढ़कर क्रमशः 31,580 रुपए और 31,430 रुपए प्रति दस ग्राम हो गया। कल सोना 210 रुपए चढ़ा था। हालांकि, सीमित सौदे के बीच आठ ग्राम वाली गिन्नी 24,800 रुपए प्रति इकाई पर ही टिकी रही। वहीं, चांदी भी सोने की राह पर नजर आई। चांदी हाजिर 690 रुपए चढ़कर 40,600 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई जबकि साप्ताहिक डिलीवरी 60 रुपए गिरकर 39,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। चांदी सिक्का लिवाल और बिकवाल क्रमशः 75000 रुपए और 76,000 रुपए प्रति सैकड़ा के पूर्व स्तर पर रहे।

ऋण शोधन कार्यवाही के तहत नियमों में संशोधन, मकान खरीदारों के लिए प्रक्रिया अधिसूचित

बिजनेस डेस्क।

ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) ने कर्ज शोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इससे मकान खरीदारों को वित्तीय कर्जदाता के रूप में राहत पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही इसमें समाधान पेशेवरों द्वारा स्पष्ट रूप से समयसीमा का पालन तथा कुछ शर्तों के साथ ऋण शोधन आवेदन वापस लेने की मंजूरी शामिल है। आईबीबीआई ने यह व्यवस्था दी है कि समाधान पेशेवरों को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कर्जदार कंपनी समाधान प्रक्रिया के दौरान निश्चित समयावधि में धोखाधड़ी वाले लेन-देन में शामिल थी। सरकार जून में ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) में संशोधन को लेकर अध्यादेश लाई थी। इसके बाद आईबीबीआई (कंपनियों के लिए ऋण शोधन प्रक्रिया) नियमन को संशोधित किया गया है। संशोधित नियमों में मकान खरीदार समेत विभिन्न श्रेणी के कर्जदाताओं के लिए प्रक्रियागत जरूरतों के मामले में अधिक स्पष्टता लाई गई है। अब समाधान पेशेवरों को यह निर्धारित करना है कि क्या कर्जदाता धोखाधड़ी वाले लेन - देन में शामिल था। साथ ही उसे यह निश्चित अवधि में निर्धारित करना है। इसके अलावा संशोधित नियमन में समाधान पेशेवरों के लिये स्पष्ट रूपरेखा रखी गई है। अब उन्हें ऋण शोधन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 75 वें दिन रूचि पत्र (ईओआई) प्रकाशित करना है। साथ ही ईओआई जमा करने की समयसीमा से 10 दिन के भीतर समाधान पेशेवरों को संभावित आवेदनकर्ताओं की अस्थायी सूची प्रकाशित करनी होगी। विज्ञप्ति के अनुसार समाधान पेशेवर संभावित समाधान आवेदनकर्ताओं की अस्थायी सूची प्रकाशित करने पांच दिन के भीतर सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन रूपरेखा तथा समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करेगा। वह समाधान योजना जमा करने के लिये कम-से-कम 30 दिन का समय देगा।

माल्या की 159 संपत्तियों की हुई पहचान

नई दिल्ली । बेंगलूर पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत से गुरुवार को कहा कि उसने शराब व्यवसायी विजय माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है। लेकिन फेरा उल्लंघन से सम्बंधित प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में पुलिस इनमें से कोई संपत्ति कुर्क नहीं कर पाई है। बेंगलूर पुलिस ने ईडी के जरिए मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत को बताया कि वह माल्या की संपत्ति कुर्क नहीं कर पाई है क्योंकि इनमें से कुछ को मुंबई क्षेत्र के ईडी ने कुर्क कर लिया है और शेष संपत्ति परिसमापन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

इस मामले में सम्मन से बचने के कारण अदालत ने चार जनवरी को माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि एजेंसी को माल्या की ऐसी अन्य संपत्तियों को पहचान करने के लिए अधिक समय चाहिए, जिन्हें कुर्क किया जा सकता है। अदालत ने एजेंसी के अनुरोध को मान लिया और बेंगलूर पुलिस को निर्देश दिया कि वह 11 अक्तूबर तक नई रिपोर्ट दाखिल करे। मट्टा ने कहा है कि बेंगलूर पुलिस ने कुर्की आदेश को तामील करने के लिए यूनाइटेड ब्रेवरीज के कानूनी सलाहकार से संपर्क किया था। यह आदेश अदालत ने मई में दिया था। कानूनी सलाहकार ने बताया कि ईडी मुंबई ने इनमें से कुछ संपत्ति जब्त कर ली है तथा अन्य संपत्ति कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए आधिकारिक परिसमापक (लिक्वीडेटर) के तहत हैं। अदालत ने आठ मई को मामले में बेंगलूर पुलिस आयुक्त के जरिए माल्या की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे और उनसे रिपोर्ट तलब की थी। अदालत ने फेरा उल्लंघन के तहत सम्मन से बचने के कारण माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया क्योंकि वह कई बार सम्मन जारी करने के बावजूद पेश नहीं हुआ। अदालत ने पिछले साल शराब व्यवसायी के विरूद्ध ऐसा गैर जमानती वारंट जारी किया था । इसके तामील करने की कोई समय सीमा नहीं होती। माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। वह किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 9000 करोड़ रुपए के ऋण बकाया तथा अन्य मामलों में भी वांछित है।

सूरत। शहर के उधना पटेल नगर में खुले प्लाट में खुदाई के दौरान हनुमानजी की मूर्ति किली थी। तीन दिन पहले की इस घटना के बाद पटेल नगर और आस-पास के निवसियों ने हनुमाजी की मूर्ति का स्थापना किया और कच्चा मंदिर बनाया था। यह मंदिर गुरुवार दोपहर को उधना जोन के स्टाफ द्वारा तोड़ दिए जाने से स्थानीय लोगों में अक्रोश फैल गया और लोगों का समूह घनास्थल पर उमड़ पड़ा। स्थिति बिगड़ते देख उधना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और लोगों को बिखेर दिया। उधना जोन के अधिकारियों द्वारा हनुमानजी का कच्चा मंदिर तोड़े जाने से स्थानीय लोगों ने आक्रोश फैला था और डिमोलिशन की इस कार्यवाही के खिलाफ विरोध व्यक्त किया।

एक ही परिवार के पांच सदस्यों का कलेक्ट्रेट पर आत्मदाह का प्रयास

राजकोट। शहर स्थित कलेक्ट्रेट पर एक ही परिवार के पांच सदस्यों के आत्मदाह के प्रयास से हड़क प मच गया। पुलिस ने परिवार के पांचों सदस्यों को हिरासत में ले लिया। आत्मदाह करनेवाले परिवार के मुखिया नरसिंहभाई सोलंकी के मुताबिक उनकी जमीन 3 बिल्डरों ने फर्जी दस्तावेज कर हड़प ली है। पिछले चार साल में कई दफा शिकायत की गई। लेकिन बिल्डरों के राजनीतिक रसूख के कारण प्रशासन ने बिल्डरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। जिससे परिवार ने आत्मदाह करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत परिवार के पांच सदस्य जिला कलेक्टर कचहरी पहुंच गए और आत्मदाह की कोशिश की। लेकिन समय रहते घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने परिवार की कोशिश को नाकाम करते हुए सभी हिरासत में ले लिया।

अहमदाबाद शहर के दरियापुर इलाके में एक गटर से भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई।

2020 तक गुजरात में 3 अरब डॉलर जापानी निवेश सुनिश्चित करेंगे: मुख्यमंत्री

- **भारत के सबसे बड़े जेट्रो के बिजनेस सपोर्ट सेंटर का विजय रूपाणी ने किया उद्घाटन**
- **जेट्रो चेयरमैन और जापान के महावाणिज्यदूत की उपस्थित रहे**

अहमदाबाद (ईएमएस)7 मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को अहमदाबाद में जापान विदेश व्यापार संगठन (जेट्रो) के बिजनेस सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन करते हुए वर्ष 2020 तक गुजरात में जापानी उद्योगों के 3 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत के इस सबसे बड़े जेट्रो बिजनेस सपोर्ट सेंटर के उद्घाटन अवसर पर जेट्रो के चेयरमैन हिरोयुकी इशिगे और जापान के मुंबई स्थित महावाणिज्यदूत रयोजी नोडा तथा राज्य के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार दास सहित कई जापानी उद्योगपति मौजूद थे।

विजय रूपाणी ने कहा कि 2003 से वाइब्रेंट समिट की सफलता में बतौर पार्टनर कंट्री सहयोगी रहे जापान के अधिकाधिक उद्योगपति और कंपनियां गुजरात में सरलता से निवेश कर सकें, इस मकसद से यह फुल फ्लेज्ड बिजनेस सपोर्ट सेंटर %राइट टाइम फॉर राइट चॉइस% है। समारोह में जापानी की 15 कंपनियों ने गुजरात के साथ %इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट% का एमओयू किया। गुजरात में निवेश और उत्पादन के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के %मेक इन इंडिया% के विजन को साकार करने में जापानी उद्योगों की सहभागिता का भरोसा व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद में इस सेंटर के शुरू होने से जापान-गुजरात के व्यावसायिक संबंध नए मोड़ में प्रवेश के साथ और भी मजबूत बने हैं। यह सफलता जापान-गुजरात दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति का निर्माण करेगी। जापानी उद्योगपतियों से मुखातिब मुख्यमंत्री ने गुजरात को भारत के विकास का रोल मॉडल बताते हुए कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गुजरात 8 फीसदी का योगदान देता है जबकि कुल औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात में गुजरात का हिस्सा क्रमश: 18 और 20 फीसदी है। इसी तरह, विदेशी पूंजी निवेश हासिल करने के मामले में गुजरात भारत के शीर्ष तीन राज्यों में से एक है। तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जापान के उद्योगकारों को गुजरात में दी जाने वाली विभिन्न सहूलियतों का मुख्यमंत्री ने विस्तार से जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापानी इकोनॉमिक कॉरिडोर को गुजरात ने %फोकस सेक्टर फॉर इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट% के तौर पर स्वीकारा है। इस कॉरिडोर की अप-डाउन दोनों तरफ की स्ट्रीम में पूंजी निवेश तथा रोजगार सृजन की विपुल संभावनाएं निहित हैं। इसके साथ ही यह जापानी कंपनियों को प्रोत्साहक वातावरण मुहैया कराएगी और गुजरात के नागरिक जीवन के कल्याण में वृद्धि करेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के 1600 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के अलावा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना, जिसका अधिकांश हिस्सा गुजरात में है, के जरिए जापानी कंपनियों को गुजरात में उत्पादित अपने प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी हिस्से में सरलता से भेजने की सुविधा मिलेगी।

रूपाणी ने गुजरात-जापान के बीच के इस सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए दोनों पक्षों के बीच नीतिगत वार्ता के ढांचे को अहम करार देते हुए कहा कि गुजरात ने हाइब्रिड इंडस्ट्रीयल पार्क, जापान-इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्यूफैक्चरिंग की स्थापना तथा अहमदाबाद के खोरज के निकट 1750 एकड़ क्षेत्र में इंडो-जापानीज इंडस्ट्रीयल टाउनशिप और ऑटो वैल्यू चेन के राज्य में निर्माण के लिए अहमदाबाद के भगापुरा क्षेत्र में निवेश इच्छुक कंपनियों को जमीन भी आवंटित की है। मुख्यमंत्री ने गुजरात में जापान सहित विदेशी निवेशकों के लिए शुरू किए गए सिंगल विंडो क्लियरेंस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुविधाओं सहित फेसेलिटेशन सेंटर्स जैसे नवीन उपक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्हें राज्य की औद्योगिक सफलता की नींव बताया। रूपाणी ने इस सेंटर की सफलता की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि जापानी उद्योगों का गुजरात में बड़े पैमाने पर आगमन सामाजिक जीवन और युवाओं सहित दुर्गम और जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए आर्थिक-सामाजिक तौर पर अवश्य लाभदायी साबित होगा।

मुंबई स्थित जापान के महावाणिज्यदूत रयोजी नोडा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जापान के साथ मैत्री संबंध विकसित करने के प्रयासों के तहत यह जेट्रो बिजनेस सेंटर कार्यरत हुआ है। इससे जापानी उद्योगपतियों और कंपनियों की सहूलियतों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि गुजरात आज निवेश का श्रेष्ठ ठिकाना बना है, इसे देखते हुए जापानी कंपनियों ने भी गुजरात में अपना निवेश बढ़ाया है। इसके चलते गुजरात के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी तथा भारत-जापान के गर्मजोशी भरे संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।

पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित दंपत्ति ने खुदकुशी कर ली

सूरत (ईएमएस)। शहर के लिंबायत क्षेत्र निवासी एक दंपत्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि दंपत्ति अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित था और इसी वजह से उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक सूरत के लिंबायत क्षेत्र के सुभाषनगर क्षेत्र निवासी 48 वर्षीय संजय पाटील ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी मीना के साथ फांसी लगा ली। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला कि संजय पाटील का पुत्र 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और उसे इंजीनियरींग कॉलेज में प्रवेश के लिए पाटील दंपत्ति प्रयासरत था। लेकिन कॉलेज की महंगी फीस ने दंपत्ति की चिंता बढ़ा रखा थी। मोटर के शोरूम में काम कर परिवार का भरण पोषण करनेवाले संजय पाटील की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इंजीनियरींग कॉलेज की महंगी फीस भर सकेंगे। जिसकी वजह से पाटील दंपत्ति अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंता था। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश की जनता रेड, पुलिस ने बताया पब्लिसिटी स्टंट

अहमदाबाद (ईएमएस)। शहर के सोला क्षेत्र में शराब पीने के बाद चार लोगों की हालत बिगड़ने के बाद चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां दो लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। इस मुद्दे को लेकर पास नेता हार्दिक पटेल, कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी एक मंच पर आ गए हैं तथा गुजरात में शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए जनता रेड का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर पुलिस ने इन तीनों नेताओं की जनता रेड को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के सोला क्षेत्र में देशी शराब पीने से चार लोगों की तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चार में से दो शख्सों की हालत गंभीर बताई गई। इस बीच हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी ने अस्पताल में उपचाराधीन इन शख्सों से मुलाकात के बाद शराबबंदी को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में पानी के पाउच बंद करानेवाली भाजपा सरकार राज्य में शराबबंदी का सख्ती से अमल करने में नाकाम रही है। गुजरात में आज भी शराब के अड्डे से धडल्ले से चल रहे हैं। पटेल, ठाकोर और मेवाणी ने ऐलान किया कि अब ऐसे शराब के अड्डों पर जनता रेड करेंगे। हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश ने आज गांधीनगर में डीसीपी कचहरी के निकट जनता रेड की। हांलाकि जिस घर में तीनों नेताओं रेड की, उस घर से कोई प्रतिबंधित वस्तु बरामद नहीं हुई। अल्पेश ठाकोर ने कहा कि गुजरात की गली गली में शराब मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को केवल हफ्तावसूली में रुचि है। पुलिस हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश मेवाणी की जनता रेड को महज एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश को उस घर से कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली। पुलिस की मानें तो वास्तव में शराब का अड्डा चलता होने का तीनों नेताओं का दावा ही गलत है।

सत्ता की लालसा में बावलिया ने भाजपा का दामन थामा : राजीव सातव

अहमदाबाद। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और सांसद राजीव सातव ने कहा कि सत्ता की लालसा में कुंवरजी बावलिया ने पार्टी से द्रोह कर भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुंवरजी बावलिया ने नई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ 50 मिनट बैठक की थी और यकीन दिलाया था कि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी का भरोसा तोड़कर भाजपा का भगवा धारण कर लिया। कुंवरजी बावलिया को जसदण विधानसभा के उपचुनाव में मतदाता सबक सिखाएंगे। भाजपा पर प्रहार करते हुए राजीव सातव ने कहा कि कांग्रेसमुक्त भारत की बात करनेवाली भाजपा गुजरात को कांग्रेसमुक्त करने में सफल नहीं हुई। यदि गुजरात में भाजपा ने अच्छे काम किए होते तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सी प्लेन उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सक्षम नहीं नेतृत्व नहीं है, इसीलिए वह कांग्रेस नेताओं को अपने साथ कर रही है। पिछले साल हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ कर लिया था। इसके बावजूद कांग्रेस और मजबूत हुई और फिर एक बार इसका पुनरावर्तन होना तय है। राजीव सातव ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकानेवाले होंगे और इस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में जो मेहनत की थी वह एक ट्रेलर था, जिसमें कई कमियां भी थीं। आनेवाले दिनों में पूरी पिक्चर सामने आएगी और पूरे देश में चौंकाने वाले नतीजे गुजरात से मिलेंगे।

लक्जरी बस और ट्रक के बीच दुर्घटना, बाल बाल बचे यात्री

सूरत (ईएमएस)। सूरत से अहमदाबाद की ओर रही लक्जरी बस और ट्रक के बीच मांगरोल रोड पर कोसंबा के बीच दुर्घटना हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरत के मांगरोल रोड पर कोसंबा के निकट नेशनल हाईवे संख्या 8 से निजी ट्रावेल्स कंपनी के लक्जरी बस यात्रियों को लेकर अहमदाबाद की ओर जा रही थी। उस वक्त सामने से आ रहे ट्रक से लक्जरी बस टकरा गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीखपुकार मच गई। हांलाकि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन 8-10 यात्रियों को छोटी-मोटी चोटें आने पर उन्हें निकट के अस्पताल भेजा गया है। खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को अब अधिक समय नहीं है तब प्रसाद के लिए मुंग को साफ करने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है।

गांधीधाम-तिरूनेलवेली साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस का शुभारंभ

अहमदाबाद। रेल मंत्री पियूष गोयल की पहल पर स्थानीय निवासियों की मांग और उनकी सुविधा के लिए ट्रेन सं या 19424/19423 गांधीधाम-तिरूनेलवेली साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस का आज गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में रेल राज्यमंत्री राजेन गोहांई ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करवाया। इस अवसर पर गोहांई ने कहा कि भारतीय रेल ने विगत चार वर्षों में काफी तरक्की की है और नई ट्रेनों को प्रारंभ किया गया है। गोहांई ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा एवं से टी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से कम हो रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद विनोद चावडा और विधायक मालती महेश्वरी भी मौजूद रहीं।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com